सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-29 अंक-18 22 सितम्बर से 6 अक्तूबर 2014 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 1 रुपया

मोदी सरकार के 100 दिन

पूँजीपतियों के आये अच्छे दिन आम लोगों के आये बुरे दिन

केन्द्र में बीजेपी सरकार बनने के 100 दिन पूरे हो गए हैं। बात यह है कि कहीं भी किसी भी मीडिया में 'बीजेपी सरकार' के 100 दिन का काम लेकर लिखा नहीं जा रहा है। सभी कह रहे हैं 'नरेन्द्र मोदी सरकार'। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा ही चाहते हैं। उनके प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद सरकार की तरफ से जो भी काम किया जाएगा, जिस सफलता का प्रचार होगा सब कुछ मोदी के नाम पर होगा। इसको लेकर इसी बीच विभिन्न सवाल उठे हैं, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री बनकर नरेन्द्र मोदी व्यक्ति एकनायकत्व कायम कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगाया गया है। इसके प्रतिवाद में सामने आए हैं प्रधानमंत्री के सहकर्मी मंत्रीगण। वे किताब लिखकर, वक्तव्य देकर बता रहे हैं कि नरेन्द्र मोदी अत्यंत जनतांत्रिक तरीके से, सामूहिक विचार के आधार पर काम करते हैं। लेकिन असल घटनाएं इतनी स्पष्ट हैं कि किताब लिखकर या वक्तव्य देकर उसे दबा देना बहुत कठिन है। एक बात साफ है कि नरेन्द्र मोदी और उसकी पार्टी मुंह से कांग्रेस की और एक समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एकनायकतांत्रिक कार्यपद्धति और स्वेच्छाचारी शासन प्रक्रिया की चाहे जितनी भी निंदा करे, सरकारी क्षमता हाथ में आने पर मोदी की पार्टी ने भी उसी रास्ते का अनुसरण करने में जरा देर नहीं लगाई।

नरेन्द्र मोदी के एकनायक बन जाने की जमीन इस बार लोकसभा चुनावों से पहले ही अत्यंत जतन के साथ सुपरिकल्पना के आधार पर तैयार की गई थी। इस परिकल्पना और उसके प्रयोग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के पीछे भारत का कारपोरेट क्षेत्र या एकाधिकारी पूंजीपति थे। महंगाई और बेरोजगारी के आघात से जब जनजीवन तबाह है, दूसरी तरफ मंदी और बाजार संकट जब पूंजीपतियों के मुनाफे की थैली पर प्रतिकूल असर डाल रहा है, तब देश के एकाधिकारी पूंजीपतियों ने ही चाहा था कि नरेन्द्र मोदी जैसे एक राजनीतिक को –जिसके पीछे एक संगठित दक्षिणपंथी पार्टी है–'सुपरमैन' के रूप में पेश किया जाए, जो जादू की छड़ी दिखाकर और विकास का जुमला उछाल कर देश के लोगों के गुस्से पर ठण्डा पानी डाल सके, 'अच्छे दिन आने वाले हैं' यह सपना दिखाकर उसकी आड़ में आवश्यक बंदोबस्त करे, जिससे एकाधिकारी पूंजीपतियों की मुनाफे की थैली भर उठें।

संसदीय जनतंत्र की आड़ में हमारे देश में जो चल रहा है वह तो बुर्जुआ तानाशाही अर्थात् एकाधिकारी पूंजीपतियों की ही तानाशाही है। यह बात तो आज एक आम आदमी भी समझता है कि देश चलता है, देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है अम्बानी-मित्तल-टाटा-बिड़लाओं के आदेशानुसार। देश की प्राकृतिक सम्पदा, जमीन के नीचे की खनिज सम्पदा, कल-कारखाने–सभी इन्हीं के कब्जे में हैं। पांच वर्षों के अंतराल में चुनावों के जरिए कौन सरकार में बैठकर एकाधिकारी पूंजी के साम्राज्य की पोलिटीकल मैनेजरी करेगा यह भी एकाधिकारी पूंजीपाति ही तय कर देते हैं। यह बात सभी जानते हैं कि नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकें, इसके लिए बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की खातिर इस बार एकाधिकारी पूंजीपतियों ने लाखों-करोड़ रुपया खर्च किया है। इसी तरह ही बीजेपी के पूर्ण बहुमत के नाम पर केन्द्र सरकार में नरेन्द्र मोदी का निरंकुश शासन कायम हुआ है। तानाशाह तो उसको होना ही होगा।

लेकिन आज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जो प्रश्न उठा है वह है, मोदी की जादू की छड़ी और विकास के आश्वासनों का परिणाम देश के लोगों के जीवन में क्या हुआ है। जनता के हालात कतई बेहतर नहीं हुए हैं यह समझने लायक बहुत लोग मोदी वाहिनी में हैं। इसीलिए नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्ववर्ती कांग्रेस के 'राइट टू फूड' की तरह एक झांसा लोगों के बीच उछाल दिया है-'जनधन योजना'। देश के करोड़ों-करोड़ लोगों के लिए बैंक खाता खोलने की व्यवस्था। रोज दो जून का खाना जुटाने के लिए देश के अधिकांश लोगों को आकाश पाताल एक करना पड़ता है। वे बैंक खाता लेकर क्या करेंगे? इसलिए कहा गया है कि बैंक खाता खोलने से 1 लाख रुपया दुर्घटना बीमा (मृत्यु बीमा), साथ ही साथ 5 हजार रुपये का कर्ज प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इससे क्या होगा? गरीब तथा मेहतनकश इंसान को आज जरूरत है ऐसी कार्य व्यवस्था की जो उसको सारा साल परिवार पालन करने जितनी न्यूनतम मजदूरी दे सके। इस का अवसर कहां है, कहां है उस नियमित आमदनी की व्यवस्था? बैंक खाता खोलना इस समस्या का कतई कोई समाधान नहीं है। इसलिए इसको झांसे के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

100 दिनों के 'सुसंवाद' के रूप में समाचार पत्रों में तथ्य प्रकाशित हुआ है–गत अप्रैल से जून तक तीन महीने में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ा है। जीडीपी का मतलब है देश में एक वर्ष में वस्तुओं और परिसेवा में कुल उत्पादन कितना हुआ है, रुपये के रूप में उसका परिमाण। कहा जा रहा है कि यह बढ़ोतरी मोदी के प्रधानमंत्रीत्व की सफलता है। आपत्ति जताते हुए कांग्रेस कह रही है–मोदी प्रधानमंत्री बने है मई महीने के अंतिम में। तब तक कांग्रेस-नीत यूपीए सत्ता में था। इसलिए जीडीपी की इस वृद्धि का श्रेय कांग्रेस को जाता है मोदी को नहीं। 'श्रेय' किसका यह लेकर दोनों पार्टियों में खींचतान चल सकती है लेकिन आम लोगों के जीवन में इस जीडीपी की वृद्धि क्या कोई सुखदायक खबर है? जीडीपी वृद्धि को लेकर जयगान 90 के दशक से शुरू हुआ था। जीडीपी वृद्धि का रिकार्ड भी इस देश मे बना है। वह देश के निचले स्तर पर करोड़ों मेहनतकश भारतवासियों के अंधकारमय जीवन में आशा की कोई किरण नहीं ला सका। उत्पादन वृद्धि का सुफल मेहनतकश आम लोगों के जीवन में तभी होता है जब उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मजदूर-कर्मचारियों की जरूरत होती है, कार्य संस्थानों की वृद्धि होती है, मेहनतकश लोग मजदूरी के बदले कुछ धन अर्जित कर पाते हैं। लेकिन आजकल की 'हाइटैक' पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ने पर भी कार्य संस्थान बढ़ते नहीं हैं बल्कि घटते हैं। इसलिए एक बात पूंजीपति ही आशंका के साथ कहते हैं-'जोबलैस ग्रोथ'। टैक्नोलॉजी की सहायता से उत्पादन क्षमता जितनी बढ़ रही है, उतना ही मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है, मालिकों का मुनाफा बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ ही मजदूरों की संख्या घट रही है। क्योंकि मजदूरों का काम मशीन या टैक्नालॉजी कर दे रही

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एसयूसीआई(सी) केन्द्रीय कमेटी की अपील

जम्मू-कश्मीर बाढ़-पीड़ितों की मदद करें

पूरा जम्मू-कश्मीर राज्य अभूतपूर्व और विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है जो एक बहुत बड़ी आपदा है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जान-माल की तबाही हुई है। इससे कश्मीर डिवीजन के श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, बारामुल्ला, बांडीपोरा व बडगाम जिलों के 45 लाख और जम्मू डिवीजन के राजौरी, पुंछ व रियासी जिलों के 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 10 दिन के प्रयास के बाद भी केवल दो लाख लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका है। जम्मू डिवीजन में अचानक आई बाढ़ से सड़क परिवहन कई जगह बाधित हो गया है और श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जगह-जगह से बह जाने के कारण अभी तक बंद पड़ा है। लोगों को पीने के पानी, खाद्य सामग्री और दवाइयों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जलजनित बीमारियाँ फैलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह अस्त-व्यस्त हैं।

मीडिया और सरकारी रिपोर्टों में अभी तक 250 लोगों के मरने की खबर है जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। महामारी न फैलने देने के लिए इसकी रोकथाम के कदम फौरन उठाने निहायत जरूरी हैं क्योंकि मवेशियों की सड़ती हुई लाशों की वजह से इसके फैलने का खतरा बना हुआ है। चूंकि बहुत सारे मकान बह गये हैं या ढह गये हैं इसलिए अनुमान है कि लगभग दो लाख लोग बेघर हो गये हैं जिनके पास न तो कोई आश्रय है और न ही पहनने और ओढ़ने-बिछाने के कपड़े हैं। ऊपर से सर्दियाँ आने वाली हैं जो इसी महीने शुरू हो जाएंगी। सर्दी के मौसम से बचाव का प्रावधान करने की संकेन्द्रित रणनीति अपनानी होगी।

मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत व बचाव कार्यों से लोग संतुष्ट नहीं हैं। घोर विपदा और दुख-तकलीफ की इस घड़ी में हम सब का फर्ज बनता है कि इस राज्य के बाढ़-पीड़ितों की मदद में आगे आयें और राहत कार्यों में हाथ बंटायें।

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से मची तबाही और लोगों की दुख-तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी ने अपने स्वयंसेवी संगठनों के जरिये जैसे पिछले साल उत्तराखण्ड में राहत कार्य किया था उसी तरह इस राज्य में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए धन और दवाइयाँ संग्रह करने का फैसला लिया है।

आप सब से अनुरोध है कि पार्टी के इस विनम्र प्रयत्न में सहयोग दें और दिल खोल कर चंदा दें।

अभिवादन सहित

प्रभाष घोष
महासचिव, एसयूसीआई(सी)

सर्वहारा दृष्टिकोण पढ़ें और पढ़ायें। लगातार इसके नये ग्राहक बनायें।

हिन्दी भाषी राज्य अपनी बकाया बिक्री राशि तुरंत जमा करायें।

सर्वहारा दृष्टिकोण के सभी पाठकों व पार्टी की राज्य कमेटियों से अनुरोध है कि पत्रिका का वार्षिक शुल्क/बिक्री राशि दिल्ली कार्यालय में तुरंत जमा करायें।

सर्वहारा दृष्टिकोण बैंक खाता नं. 522000100360826
IFSC Code & PUNB 0152200,
पंजाब नैशनल बैंक, राजेन्द्र प्लेस शाखा, नई दिल्ली।
प्रबंधक, सर्वहारा दृष्टिकोण

मोदी सरकार के 100 दिन ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

है। मालिक लोग भी निरंतर उत्पादन बढ़ाने के लिए नित नई टैक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल कर रहे हैं, मजदूरों की जरूरत घट रही है। नए मजदूरों की भर्ती तो दूर की बात, जो काम पर हैं उनकी भी छंटनी कर रहे हैं। एक आंकड़ा देने से साफ-साफ समझा जा सकेगा। भारत में 1972 से 1978 तक जीडीपी वृद्धि दर जब 4.6% थी, तब कार्य संस्थान 2.6% की दर से बढ़े थे। लेकिन 1993 से 2000 तक जीडीपी जब 6.5% की दर से बढ़ा तब कार्य संस्थान मात्र 1% ही बढ़े थे। 2004 से 2010 तक जीडीपी की वृद्धि 9.8% लेकिन कार्य संस्थान सिर्फ 0.2% ही बढ़े। (योजना पत्रिका, अक्टूबर 2013) इसके नतीजतन आय रहित लोगों की संख्या बढ़ रही है जिसका मतलब है खरीददार घट रहे हैं। नतीजतन उत्पादित माल जमा होने से अति उत्पादन की समस्या घनघोर हो रही है, बाजार संकट बढ़ने से मंदी स्थाई रूप ले रही है। महान मार्क्स द्वारा प्रदर्शित पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था के इस अंतर्निहित द्वंद्व-संघात ने आज प्रचण्ड रूप लेकर पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को ही गहन संकट में डाल दिया है, जिसका समाधान करना पूंजीवाद के लिए संभव नहीं है। इस हालत में जीडीपी वृद्धि के आंकड़े दिखाकर मुठ्ठीभर सुविधाभोगी अमीरों और मालिक वर्ग की शाबाशी हासिल की जा सकती है लेकिन देश के करोड़ों-करोड़ बेरोजगार युवा शक्ति (शिक्षित और शिक्षा से वंचित दोनों ही) के हितों की रक्षा नहीं हो सकती है।

भारत जैसे देश में वोट के बाजार में गरीब लोगों की बात, मजदूरों की बात, गरीब किसानों की बात न करने से वोट नहीं मिलती हैं। इसीलिए पूंजीपति वर्ग की ताबेदार अति दक्षिणपंथी पार्टी को भी वोट के बाजार में जन स्वार्थ रक्षा की, जनता का विकास करने की बात कहनी पड़ती है। मोदी ने भी कही है। उनका 'अच्छे दिन' तो एक जुमले में तब्दील हो गया है। लेकिन प्रथम बजट में क्या देखा गया? मोदी ने घोषणा की है कि देश भर में वे 'स्मार्ट सिटी' या 'चमचमाते शहर' बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चालू करेंगे, बड़ी-बड़ी बंदरगाह तैयार होंगी इत्यादि-इत्यादि। लेकिन जिस देश में कृषि आज भी वर्षा पर निर्भर है, सूखे और बाढ़ से जहां फसलें नष्ट होना एक नियमित घटना है वहीं सिंचाई कार्य के लिए मोदी सरकार का आवंटन मात्र 1 हजार करोड़ रुपया है। फिर, बंदरगाह निर्माण के लिए आबंटित किया गया है 10 हजार करोड़ रुपया। इसी तरह शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट आबंटन नगन्य है। यह बात समझना भी कठिन नहीं है कि स्मार्ट सिटी, हाइवे, बंदरगाह इत्यादि जो भी हो उनके निर्माण का मायने ही है जमीन-बस्ती से और भी हजारों-हजार लोगों को उजाड़ देना। इसका रास्ता साफ करने के लिए ही शायद भूमि अधिग्रहण कानून को और भी सरल बनाने की जोड़-तोड़ में लगी है मोदी सरकार।

मोदी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर जो और एक बात बड़ी होकर सामने आ रही है वह है देश की सामाजिक परिस्थिति, विशेषकर साम्प्रदायिक सद्भाव का प्रश्न। गत लोकसभा चुनावों से पहले 'विकास' के नारे के साथ-साथ किस प्रकार जनजीवन में साम्प्रदायिक फूट पैदा करने का हथकण्डा बीजेपी ने अपनाया था वह अब प्रकट रूप से सामने आ गया है। इस बार कई राज्यों में उपचुनाव से पहले छांट-छांट कर उन्हीं चुनाव केन्द्रों पर ही साम्प्रदायिक उत्तेजना पैदा कर दंगे उकसाए और दंगे भड़का भी दिए। ये घटनाएं साबित करती हैं कि 'विकास' की बातें कुछ मंदी पड़ते ही, रेल भाड़ा वृद्धि, महंगाई की मार से लोगों का मोह भंग होना शुरू होते ही बीजेपी और संघ परिवार ने साम्प्रदायिकता का तुरूप का पत्ता खेलने का सहारा लिया है। मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में कहा था, '10 साल के लिए साम्प्रदायिक दंगे-फसादों पर रोक लगाइये, दूसरी तरफ आरएसएस और बजरंग दल हिन्दुत्व के प्रचार और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने के लिए मैदान में उतर गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का नया हथियार है 'लव जेहाद'। मुजफ्फरनगर के दंगों का सूत्र पकड़कर बीजेपी का यह नया प्रचार है जो यह कहने की जरूरत नहीं है कि अल्पसंख्यकों के प्रति विद्वेष की आग में ईंधन डालकर सद्भावना के माहौल को खराब करेगा।

अब जनता ही विचार करे कि मोदी सरकार के 100 दिन जन जीवन में क्या संदेश लेकर आए हैं।

बिहार राज्यपाल कार्यालय के समक्ष छात्रों का विशाल प्रदर्शन

पटना : छात्रों के जनवादी अधिकारों पर हो रहे हमलों पर रोक लगाने, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजकता पर रोक लगाने, स्कूलों में पास-फेल प्रथा को पुनः लागू करने, सेमेस्टर सिस्टम पर रोक लगाने, फीस वृद्धि एवं शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण पर रोक लगाने जैसे ज्वलंत शैक्षिक सवालों को लेकर 10 सितम्बर को ऑल इंडिया डीएसओ बिहार राज्य कमिटी ने राज्यपाल के समक्ष छात्रों का विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बिहार के विभिन्न जिलों के स्कूल-कॉलेजों से आये हजारों छात्र गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास से भारी बारिश में जुलूस के रूप में बढ़ते हुए डाक बंगला होकर आर. ब्लॉक गये। छात्र पूरे रास्ते छात्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे। आर. ब्लॉक के पास पहुंच कर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता ऑल इंडिया डीएसओ के राज्य अध्यक्ष सूर्यकर जितेन्द्र ने की।

सभा को सम्बोधित करते हुए ऑल इंडिया डीएसओ के महासचिव अशोक मिश्रा ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के जरिये अच्छे दिन आने का जो सपना दिखाया था, वह आज पूरी तरह व्यर्थ है। उनकी सरकार भी पिछली सभी सरकारों की तरह ही जनविरोधी एवं छात्र-विरोधी नीतियाँ ही लागू कर रही है। शिक्षकों के 9 लाख से भी अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। आरएसएस की विचारधारा की वकालत करने वाले दीनानाथ बतरा के घोर अवैज्ञानिक, दकियानूसी, साम्प्रदायिक व गये-बीते प्रवचनों को गुजरात में लागू किया जा रहा है और देश भर में भी चालू किया जाना है। शिक्षा का निजीकरण कर इसे इतना महंगा बनाया जा रहा है कि यह छात्रों की पहुंच से दूर होती जा रही है। सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रों और शिक्षकों पर फासीवादी हमले हो रहे हैं। पिछले दो महीने से पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र आंदोलन चल रहा है, छात्र लाठी-गोली खा कर भी अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। अशोक मिश्रा ने अधिकारों को पाने के लिए आंदोलन गठित करने पर जोर दिया।

सभा को ऑल इंडिया डीएसओ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष गोपाल साहु, बिहार राज्य सचिव अनिल कुमार, उपाध्यक्ष विकास कुमार, सचिव मंडल सदस्य रौशन कुमार, दरभंगा के लाल कुमार, पटना के सरोज कुमार सुमन, मुजफ्फरपुर के आशुतोष कुमार, शिवचन्द्र पासवान, अरवल के दीपक कुमार इत्यादि ने भी संबोधित किया।

बिहार राज्य उपाध्यक्ष रौशन कुमार के नेतृत्व में दस सदस्यों के शिष्ट मंडल ने राज्यपाल को मांग-पत्र सौंपा।

शिक्षक दिवस पर स्कूलों में मोदी के सम्बोधन के सीधे प्रसारण का विरोध

मुरादाबाद (उ.प्र.) : शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीधे सम्बोधन को सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से प्रसारण के खिलाफ ऑल इण्डिया डीएसओ ने 4 सितम्बर को जिलाधिकारी कार्यालय, मुरादाबाद पर विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए केजीके कॉलेज मुरादाबाद के प्रो. डॉ. चन्द्रभान यादव ने मोदी के सम्बोधन के प्रसारण को गैर जनवादी और शिक्षा के साम्प्रदायिकीकरण करने वाला कदम करार दिया। कॉ. ऋतु चौधरी, कॉ. फैज खान, उपासना राजपूत, मंजू मेहता, सन्नी खान, मौ. गौरी व एआईडीवाईओ के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह ने भी सभा को सम्बोधित किया।

मुरादाबाद में सड़कों पर उतरे छात्र

शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ स्कूल-कालेज छात्रों का सम्मेलन

आरोन(म.प्र.) : शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ 27 जुलाई को यहां छात्र संगठन एआईडीएसओ द्वारा स्कूल व कॉलेज छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें उच्च शिक्षा में समेस्टर प्रणाली, एकल प्रश्न प्रणाली, विश्वविद्यालय द्वारा जारी भारी भ्रष्टाचार एवं परीक्षा परिणामों में की गई धांधली के खिलाफ और प्राथमिक शिक्षा स्तर में कक्षा आठवीं तक बेरोकटोक पास करने की नीति एवं पाँचवीं-आठवीं बोर्ड हटाने के विरोध में छात्रों ने अपनी बात रखी। सम्मेलन का संचालन भास्कर रघुवंशी ने किया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष सचिन जैन ने शिक्षा-विरोधी, छात्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ छात्रों को एकजुट होकर शिक्षा को बचाने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ने की अपील की।

छात्र सम्मेलन में किसान आत्महत्या पर निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया और इनकी रोकथाम करने के लिए उचित कदम उठाने की सरकार से मांग की गई। संगठन के जिला सचिव मनीष श्रीवास्तव द्वारा ग्राम बनखेड़ी में हुई किसान आत्महत्या में सरकार की किसान-विरोधी नीतियों को दोषी मानते हुए इन नीतियों को तुरंत रद्द करने की मांग की।

सम्मेलन को संगठन के जिला उपाध्यक्ष योगेश धाकड़, नगर प्रभारी तेजभान साहू, विजय जाटव व महेन्द्र नायक ने भी सम्बोधित किया।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया फीस वृद्धि का विरोध

जौनपुर (उ.प्र.) : बी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा की गई बेतहाशा फीस वृद्धि, समय पर रिजल्ट न घोषित करने व सीट न बढ़ने के खिलाफ 25 अगस्त को विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों का हुजूम छात्र संगठन एआईडीएसओ के बैनर तले विश्वविद्यालय पहुँचा। जासोपुर बाजार से जोरदार नारे लगाते हुए मुख्यद्वार से होते हुए परिसर पहुँचकर प्रशासनिक भवन के समाने छात्र सभा की गई। सभा को संगठन के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार, टी.डी. कॉलेज छात्र के पुस्तकालय मंत्री व संगठन के कॉलेज इकाई के सचिव विशाल कुमार मौर्या ने सम्बोधित किया । संचालन टी. डी. कॉलेज इकाई अध्यक्ष रामआशीष ने किया। संगठन के जिला सचिव विकास ने जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक छात्र आन्दोलन जारी रखने का आह्वान किया। कुलपति की अनुपस्थिति में प्रॉक्टर ने अपने सहयोगियों के साथ आकर ज्ञापन लिया और छात्रों को शीघ्र निदान का आश्वासन दिया। इसके पहले टी.डी. कॉलेज से जेसीज चौराहे तक छात्रों ने जुलूस निकाला।

बड़ोदरा में मेडिकल सर्विस सेंटर द्वारा लगाये गये मेडिकल कैम्प में मरीजों को देखते हुए डाक्टरों की टीम

यू.पी. में साम्प्रदायिकता में आया उछाल

उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिकता की भट्टी में तब्दील हो गया है। समुदायों का ध्रुवीकरण करते हुए साम्प्रदायिक हिंसा राज्य में व्याप्त है जिसके लिए आक्रामक बीजेपी और कमजोर तथा निकम्मी समाजवादी पार्टी दोनों ही राज्य को एक जिंदा बम में परिणत करने के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं जो कभी भी फट सकता है।

लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के दिन 16 मई से उत्तर प्रदेश में कम से कम 24 दंगे भड़क चुके हैं। इन दंगों में 8 लोग मारे जा चुके हैं और 250 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें से लगभग आधे दंगे धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल या जुलूसों में पटाखे चलाने जैसे तुच्छ मुद्दों को लेकर हुए हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि इनमें से ज्यादातर दंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं इस क्षेत्र में वे आधी विधानसभा सीटें पड़ती हैं जहाँ नवम्बर में उप चुनाव होने हैं। जो सीटें बीजेपी विधायकों के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई हैं उन 12 विधानसभा क्षेत्रों में ये उप चुनाव होने हैं। इन 12 सीटों में से 6 में पिछले ढाई महीनों में साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं। विधानसभा क्षेत्रवार लोकसभा चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि इन 6 में से चार सीटें ऐसी हैं जिनमें यूपी के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा।

6 जुलाई को मुरादाबाद में जब एक मंदिर से पुलिस द्वारा लाउडस्पीकरों को हटाने के खिलाफ प्रतिवाद में एक पंचायत करने का प्रयास करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए तब डी एम सहित 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीजेपी के एक विधायक कुवंर सर्वेश सिंह समाजवादी पार्टी के एच.टी.हसन को 87000 से अधिक मतों से हरा कर सांसद चुने गये हैं जिससे मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में उपचुनाव होने हैं। विधानसभा क्षेत्रवार लोकसभा चुनाव परिणाम दर्शाता है कि तीन विधानसभा क्षेत्रों में श्री सिंह और दो विधानसभा में हसन आगे थे। असल में ठाकुरद्वारा में श्री सिंह 475 वोटों से श्री हसन से पीछे थे। यदि यह विधानसभा चुनाव होता तो वे यहाँ से हार जाते।

इसी प्रकार, सहारनपुर में 26 जुलाई को हुए साम्प्रदायिक दंगों में तीन लोग मारे गये। कुछ इलाकों में आज तक भी कर्फ्यु जारी है। बीजेपी के राघव लखन पाल सहारनपुर से लोकसभा चुनाव जीते हैं। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटों में मिस्टर पाल तीन में और कांग्रेस के इमरान मसूद दो में आगे थे। सहारनपुर नगर क्षेत्र में मिस्टर पाल मात्र 23,784 वोटों से आगे थे।

बीजेपी के विधायक हुकुम सिंह के सांसद चुने जाने के बाद कैराना की सीट खाली हुई थी। लोकसभा क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटों में से कैराना में मतों का अंतर सबसे कम 26,629 था। शामली में 5 जून को दंगे-फसाद हुए और मुजफ्फरनगर में 11 और 13 जुलाई को साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ। इसी प्रकार बिजनौर में बीजेपी विधायक भारतेन्दु सिंह सांसद चुने गए। हुक्म सिंह और भारतेन्दु सिंह दोनों ही मुजफ्फरनगर दंगों में भी अभियुक्त हैं जिनमें 65 से अधिक लोग मारे गए थे और 65000 विस्थापित हुए थे।

बहराइच के बलहा और गौतमबुद्ध नगर में नोएडा में भी उपचुनाव होने हैं। ये सीटें बीजेपी विधायकों साबित्री बाई फुले और महेश शर्मा के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई हैं। जहाँ बहराइच में 25 मई को साम्प्रदायिक दंगे हुए वहीं गौतमबुद्ध नगर में 30 जून को दंगे हुए।

समुदायों का ध्रुवीकरण मौजूदा आपसी भाईचारे व सद्भाव को तोड़ सकता है जिसके चलते गैर-मुस्लिम वोटों का सुदृढ़ीकरण हो सकता है। पूरे राज्यभर में मतदाताओं पर मुजफ्फरनगर हिंसा का प्रभाव पड़ने से राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 71 बीजेपी को हासिल हुईं। इसके अतिरिक्त सैकड़ों घटनाएं घटी, हालांकि उनकी खबर राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आई, जिन्होंने इस ध्रुवीकरण को बढ़ाने में मदद दी जिसे राज्य में तमाम गैर बीजेपी दलों द्वारा महसूस किया गया था।

इनमें एक नया तत्व जुड़ गया है। 'लव जेहाद' को केन्द्र करके जहर फैलाया जा रहा है जिसमें दो विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम प्रसंगों, छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या की कहानियाँ जिनमें से ज्यादातर असत्यापित हैं–जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। इनका परिणाम यह हो रहा है कि हर कोई एक-दूसरे के खून का प्यासा बन गया है और जिनका कोई दीन-ईमान नहीं ऐसे राजनेता असल में इसको सुनिश्चित कर रहे हैं जैसाकि मुजफ्फरनगर के मामले में हुआ। मेरठ में कथित बलात्कार अब एक अहम मुद्दा बन गया है जिसमें पीएसी असल में बस्तियों में लोगों को यह कहती फिर रही है कि 'सुरक्षित' स्थानों पर चले जाओ।

यह लगभग ऐसा है मानो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके खतरे को लगता है कि कोई नहीं समझ रहा है या समझना नहीं चाह रहा है कि साम्प्रदायिक ताकतें जो फूटपरस्त और नफरत भरी राजनीति के जरिए पैर फैला रही हैं, इनका बहुत कम या कोई विरोध न रहने के चलते साम्प्रदायिकता का प्रसार लगभग संस्थापित होता जा रहा है। धरातल पर अभागे लोगों द्वारा इस जहर का असर महसूस किया जा रहा है जिनकी असुरक्षा का खतरा बढ़ गया है इस अहसास के साथ कि राज्य में उनके लिए कोई सरकार नहीं है जो राज्य के जिलों में शांति और सदभाव कायम करने की इच्छुक हो या सक्षम हो।

कोई कानून का राज या जवाबदेही यहाँ नहीं है। वस्तुतः लोगों को झूठ-फरेब की दलदल में धंस जाने के लिए खुद के भरोसे छोड़ दिया गया है कि वे वास्तविकता से दूर परछाइयों पर प्रतिक्रिया करते रहें। बीजेपी इस क्षेत्र मे आक्रामक है और बिना किसी रोकटोक या बाधा के बेलगाम हो गई है जबकि समाजवादी पार्टी सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ है और दुनिया के इस हिस्से में हालात सामान्य करने के लिए ठोस कदम उठाने में या तो अक्षम है या अनिच्छुक है। स्थानीय मीडिया की भूमिका की भी जांच-पड़ताल करने और इसे दुरस्त करने की जरूरत है क्योंकि तथ्यों की बजाए झूठी अफवाहें प्रेषित करने का रुझान है। नितांत अतिरंजित रिपोर्टें आग में घी का काम करती हैं और तनाव को और भी बढ़ा देती हैं।

राज्य में कानून-व्यवस्था की रक्षा करने में नाकाम रहने के लिए बीजेपी अखिलेश यादव सरकार की कटु आलोचना कर रही है। बीजेपी के नेतागण क्यों इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या भारत के सबसे बड़े राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है?

मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद दो महीनों से भी ज्यादा अर्से से उत्तर प्रदेश में बेलगाम अपराध और अराजकता देखी जा रही है। श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में वस्तुतः सैकड़ों साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं। मुस्लिमों और जाटों के बीच दंगों के बाद मुस्लिमों और सिखों के बीच दंगे हुए हैं। मोदी सरकार को लगता है अपनी जिम्मेदारियों का कोई अहसास ही नहीं है। बीजेपी पर राजनैतिक खेल खेलने से बाज आने और समाजवादी पार्टी सरकार पर जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई भी दबाव नहीं है। राज्य में साम्प्रदायिक सदभाव और मेलजोल बहाल करने के लिए यूपी में तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। (8.8. 2014 के टाइम्स ऑफ इण्डिया और द स्टेटसमैन से संकलित)

कॉ. शिवदास घोष स्मृति सभाएं आयोजित

रोहतक में सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. शंकर साहा

हरियाणा : 10 अगस्त को रोहतक के जाट भवन सभागार में दिवंगत नेता, एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव, इस युग के महान् मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉ. शिवदास घोष की 38वीं बरसी पर स्मृति सभा की गई। सभा की अध्यक्षता पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य और हरियाणा राज्य सचिव कॉ. सत्यवान ने की। पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. शंकर साहा मुख्य वक्ता रहे। कॉ. शंकर साहा ने कहा कि आज शोषण और लूट एक बुनियादी मुद्दा है। कॉ. घोष छोटी सी उम्र में ही आजादी आन्दोलन में कूद पड़े थे ताकि एक ऐसी समाज व्यवस्था लाई जा सके जिसमें शोषण-लूट न रहे। जैसा कि रूस में हुआ। आजादी आन्दोलन के दौरान कॉमरेड घोष ने जब देखा कि देश के नौजवान, आम लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनका सारा फल पूंजीपति वर्ग हड़प लेगा, आम आदमी शोषित ही रह जाएगा। अगर उस समय देश में सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी होती तो देश का इतिहास कुछ और ही होता। सीपीआई थी लेकिन केवल नाम के लिए कम्युनिस्ट थी। क्योंकि लेनिन की सीख के मुताबिक एक सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी के बिना क्रान्ति नहीं हो सकती है। कॉ. घोष ने 1948 में एसयूसीआई (सी) की स्थापना की।

कॉ. साहा ने कहा कि आजादी के बाद देश में पूंजीपतियों का राज कायम हुआ। पहले कांग्रेस शासन करती थी अब बीजेपी की मोदी सरकार शासन में है। हमारे देश में ज्यादातर पार्टियां पूंजीपति वर्ग की हैं। जिस भी बुर्जुआ पार्टी की सरकार आये वह इस पूंजीवादी शासन-शोषण को ही पक्का करेगी। सरकार पूंजीपति वर्ग की दरबान, उसकी पोलिटीकल मैनेजर होती है। आज मजदूर आन्दोलन पर, जन आन्दालन पर भयंकर हमले, दमन, जुल्म आने वाले हैं। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने कानून में संशोधन किया है कि 300 मजदूरों तक को नौकरी से निकालने के लिए मालिकों को कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी।

कॉ. साहा ने कहा कि जनआन्दोलन के अंग के तौर पर ही हम चुनाव में जाते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि चुनाव से सरकार बदलती है लेकिन सत्ता दखल नहीं होता है। कांग्रेस, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकण्डे अपनाती हैं, दलबदल कराती हैं, सत्ता में आकर वही पूंजीपतिपरस्त नीतियां लागू करती हैं। उनमें मूल में कोई फर्क नहीं है। इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनआन्दोलन ही सही रास्ता है। जनकमेटियां बनायें। जनआन्दोलन गठित करें। नौजवानों को जनआन्दोलन की मुख्य धारा में लायें। तभी समाज बदलेगा।

मध्य प्रदेश : कॉ. शिवदास घोष स्मृति दिवस पर 7 अगस्त को गुना जिले की आरोन तहसील में हुई सभा में भारी बारिश के बावजूद गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, इन्दौर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, शिवपुरी जिलों से सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ता आये। मुख्य वक्ता पार्टी के दिल्ली राज्य प्रभारी कॉ. प्रताप सामल ने दिखाया कि किस प्रकार उन्होंने भारत की सरजमीं पर क्रांति के सिद्धांत को मूर्त रूप देकर मार्क्सवाद के ज्ञान भंडार में बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों का वादा करके आई नरेन्द्र मोदी सरकार ने असल में जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले से देश में बढ़ती किसानों की आत्महत्याओं, विकराल रूप लेती महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए न केवल इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया बल्कि सत्ता में आते ही पूंजीपतियों पर मेहरबानियों की बौछार कर रेल किराये-मालभाड़ा और डीजल-पेट्रोल महंगा कर जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने देश में हर क्षेत्र में बढ़ते फासीवाद के खतरे की विस्तार से चर्चा करते हुए वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इन परिस्थितियों का एक ही हल है कि हर घर में शिवदास घोष का साहित्य पहुँचायें और भारत में पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति लाने के संघर्ष में जनता का वैचारिक स्तर उन्नत करते हुए खुद की सीमाबद्धताओं से भी संघर्ष करें। कार्यक्रम को पार्टी के स्थानीय सचिव कॉ. प्रदीप आर.बी और गुना जिला कमेटी सदस्य कॉ. लोकेश शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के ग्वालियर जिला सचिव कॉ. सुनील गोपाल ने की।

सागर (म.प्र.) : 5 अगस्त को पार्टी के तिली कार्यालय में एस.यू.सी.आई. (सी) सागर जिला ईकाई के तत्वावधान में इस युग के महान् मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉ. शिवदास घोष की बरसी पर सभा की गई। सभा की अध्यक्षता पार्टी के राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य कॉ. रामावतार शर्मा ने की। पार्टी राज्य सचिव कॉ. उमा प्रसाद मुख्य वक्ता रहे। सभा का संचालन पार्टी के राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य कॉ. अशोक कुशवाहा ने किया और गणेश पटेल व राकेश पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing :20 September, 2014

श्रमिकों का राष्ट्रीय कन्वेन्शन

दिल्ली में श्रमिकों का राष्ट्रीय कन्वेन्शन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड शंकर साहा

नई दिल्ली : कई राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन की एकतरफा पहल, रक्षा क्षेत्र सहित बैंक, बीमा, रेलवे व अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण और विनिवेशीकरण के खिलाफ 15 सितम्बर को कॉन्स्टीच्यूशन क्लब एनेक्सी में श्रमिकों का राष्ट्रीय कन्वेन्शन हुआ। इसका आयोजन ऑल इण्डिया यूटीयूसी समेत 11 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त बैनर तले किया गया। संयुक्त अध्यक्षमण्डल ने कन्वेन्शन का संचालन किया जिसमें ऑल इण्डिया यूटीयूसी के सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड सत्यवान भी थे। अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं के अलावा ऑल इण्डिया यूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा ने कन्वेन्शन को सम्बोधित किया।

कॉमरेड साहा ने कहा कि श्रमिकों की लड़ाई किसी सरकार या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि श्रमिक-विरोधी नीतियों के खिलाफ है। क्योंकि सरकार बदल जाती है लेकिन नीतियाँ नहीं बदलती। ऊपर से देखने में लगता है सरकार नीतियाँ बनाती है लेकिन असल में नीतियाँ बनाते हैं एकाधिकारी पूँजीपति घराने, मिलिटरी, अफसरशाह। पूँजीपति ही सरकार बनाते हैं और वे ही नीतियाँ बनाते हैं। इस शोषणमूलक व्यवस्था जिसमें आदमी का शोषण होता है, जिस मशीन से शोषण होता है, वह बदले बिना शोषण खत्म नहीं होगा। एक महापुरुष ने कहा है कि शोषण नहीं होता तो शासन की भी जरूरत नहीं पड़ती, राजसत्ता की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेड यूनियन आन्दोलन की ताकत को बढ़ाने के लिए हम दिल्ली में जमायत करते हैं। ताकत तो बढ़ी लेकिन जुल्म कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। इसके लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। हालांकि यह बात हम बोलते नहीं हैं। यह मजदूर आन्दोलन की अन्दरूनी कमजोरी है। मैं 1969 में एक संयुक्त प्रदर्शन में दिल्ली आया था। उस समय भी नारा था 'इन्दिरा तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं'। आज 45 साल बाद हालत और भी बदतर हो गई है। इसलिए सही दिशा में लड़ना है। राजसत्ता के खिलाफ लड़ना है। जैसे लोकसभा चुनाव के समय नारा दिया गया 'अच्छे दिन आने वाले हैं'। अच्छे दिन पूँजीपतियों के आये हैं। हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। संविधान में हर आदमी को शोषण करने का, मुनाफा कमाने का अधिकार दिया गया है। पूँजीपतियों के इस मुनाफे के अधिकार को ही आगे बढ़ाने में जुटी हैं इनकी तमाम ताबेदार पार्टियां और इसी की रक्षा करती है राजसत्ता। सवाल यह है कि हम मजदूर आन्दोलन को सही रास्ते पर ले जायेंगे या नहीं। वर्ना कन्वेन्शन होगा, जमायत होगी, हड़ताल होगी लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। इन्कलाब जिन्दाबाद, बंदे मातरम के नारे लगाये जायेंगे लेकिन मजदूर और भी भूखा-नंगा होता जायेगा। आपसे अपील है कि आन्दोलन की एकता को निचले स्तर तक ले जाइये। आप मजदूरी करते हैं अगर आप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, बेइज्जती महसूस होती है तो आगे आइये, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाइये। क्रान्तिकारी बधाई देते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया।

सम्मेलन में सितम्बर-अक्तूबर के दौरान राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेन्शन करने और 5 दिसम्बर को सभी राज्यों की राजधानियों में संयुक्त प्रदर्शनों के जरिये प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

एआईएमएसएस ने उपराज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

दिल्ली : शांतिवन इलाके में एक नाबालिग लड़की के यौन-उत्पीड़न और उस घटना का विरोध करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन डा. मोहिनी गिरी पर हुए हमले पर रोष जताते हुए ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की दिल्ली राज्य कमेटी की ओर से 2 सितम्बर को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नसीब जंग को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि नाबालिग लड़की का यौन-उत्पीड़न करने वाले और डा. मोहिनी गिरी पर हमला करने वाले अपराधियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए और डा. गिरी की मदद करने से इनकार करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

ज्ञापन देने गये चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कॉ. सीता सिंह ने किया।

कॉमरेड बादशाह खान लाल सलाम

हमारी प्रिय पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के वरिष्ठ नेता, वर्धमान जिला कमेटी के पूर्व सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी एवं मध्य प्रदेश कॉऑर्डिनेटिंग कमेटी के पूर्व सदस्य, वामपंथी आन्दोलन एवं श्रमिक आन्दोलन के नेता कॉमरेड शुभाशीष सेन (बादशाह खान) कैन्सर सहित और भी कई बीमारियों से लम्बे अर्से से पीड़ित थे। उन्होंने 30 अगस्त को सुबह 8 बजे निन्द्रावस्था में अन्तिम साँस ली। वे 81 वर्ष के थे।

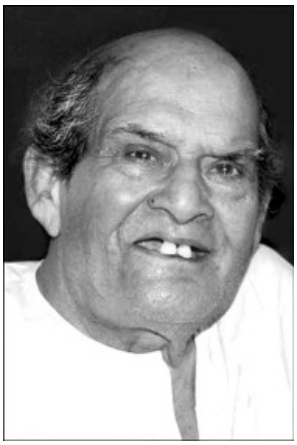

1948 में पार्टी स्थापना के लगभग बाद ही कॉ. बादशाह खान 1950-51 में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के तत्कालीन नेता कॉमरेड मनोरंजन बैनर्जी से सम्पर्क होने पर उनके माध्यम से सर्वहारा के महान नेता, इस युग के अन्यतम श्रेष्ठ मार्क्सवादी दार्शनिक व चिन्तक कॉमरेड शिवदास घोष के सानिध्य में आये और कॉमरेड घोष के क्रान्तिकारी चिन्तन से अनुप्राणित होकर पार्टी के साथ जुड़े।

वे अमीर खानदान की संतान थे और एशो-आराम से पले थे। लेकिन महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं ने उनको तमाम एशो-आराम त्याग कर ऊपर से देखने में कष्टों भरे क्रान्तिकारी जीवन को हँसते-हँसते आनन्द के साथ अपनाने के लिए प्रेरित किया था। कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं के आधार पर कॉमरेड बादशाह खान ने अपने व्यवहार से पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों सहित सामान्य लोगों को क्रांति व पार्टी के प्रति अनुप्राणित करते हुए उन पर ऊँची नीति नैतिकता की छाप छोड़ी थी। पार्टी जीवन की शुरूआत में कोलकाता के खिदरपुर इलाके में पार्टी का काम किया। खिदरपुर बार्ड कम्पनी के श्रमिकों की यूनियन के वे सहसचिव और फिर सचिव बने। कोलकाता के बेलेघाटा में पार्टी संगठन व कई ट्रेड यूनियनों का निर्माण किया। 1965 में उन्हें वर्धमान जिला के दुर्गापुर में पार्टी संगठन की जिम्मेदारी देकर भेजा गया। साथ-साथ वे बाँकुड़ा जिला में भी पार्टी बनाते रहे। कॉ. बादशाह खान को 1983 में पार्टी के निर्देश पर पार्टी संगठन व ट्रेड यूनियन के काम के लिए दिल्ली भेजा गया। दिल्ली के ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया में मजदूरों को संगठित किया, यूनियन बनाई और मजदूरों की मांगों को हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण आन्दोलन किये। 1989 में केन्द्रीय कमेटी ने उनको मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन का विस्तार करने के काम से भेजा। 1998 में उनको छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन की जिम्मेदारी देकर भेजा गया था। 1988 में पार्टी की पहली पार्टी कांग्रेस में वे पार्टी के स्टाफ सदस्य बने। कॉ. बादशाह खान अतयंत सहज-सरल, सहानुभूतिशील और उदार मन के थे। पार्टी के प्रति उनकी वफादारी प्रश्नातीत थी। वे अत्यंत स्नेहप्रवण थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनमें मां जैसी ममता थी। बड़े जतन से उन्होंने कार्यकर्ता तैयार किये हैं। गरीबों को वे जी-जान से प्यार करते थे। वे बस्ती के गरीबों से लेकर बहुत पढ़े-लिखे लोगों तक अनायास ही घुलमिल जाते थे। अपने चारित्रिक गुणों से उनको पार्टी की ओर आकर्षित कर लेते थे और हमदर्द, समर्थक और कार्यकर्ता में तब्दील कर देते थे। क्रान्तिकारी उद्देश्यमुखीता और चरित्र के माधुर्य से वे सबका दिल जीत लेते थे। प्रतिकूल परिवेश में पार्टी निर्माण के लिए उन्हें अनथक व कठोर मेहनत करते हुए सभी ने देखा था, वे सभी पूरी श्रद्धा से उन्हें याद कर रहे थे। 30 अगस्त को उनकी मृत्यु से पार्टी ने एक क्रान्तिकारी नेता खो दिया।

अगले दिन उनके पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक लाल झंडे में लपेटकर पार्टी सेंटर में अंतिम दर्शन व श्रद्धांजली के लिए रखा गया। पार्टी के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष की ओर से केन्द्रीय समिति सदस्य कॉ. गोपाल कुण्डु ने, पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. असित भट्टाचार्य की ओर से कॉ. विश्वजीत हारोडे ने व कॉ. गोपाल कुण्डु ने अपनी ओर से माल्यार्पण कर उनके प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की। इसके पश्चात दुर्ग जिला कमेटी इंचार्ज कॉ. विश्वजीत हारोडे, सदस्य कॉ. संध्या राय, कॉ. आत्मा राम साहू, कॉ. महेन्द्र साहू, कॉ. देवेन्द्र पाटिल, कॉ. निवास अधिकारी ने माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजली दी। साथ ही वयोवृद्ध वामपंथी कार्यकर्ता श्री अकोजवार, सामाजिक कार्यकर्ता व मजदूर नेता कॉ. ज्ञानेश दुबे, प्रो. जे.पी. साव, पत्रकार श्री उल्हास ठोके, समर्थक श्री अब्दुल फरीद, मुकेश राय, श्री के.एल. साहू सहित अनेक लोगों, पार्टी व जन संगठनों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों ने फूल चढ़ाकर कॉमरेड बादशाह खान को अपनी श्रद्धांजली अर्पित की।

इसके पश्चात शोकाकुल कॉमरेडों ने उनके पार्थिव शरीर को, उनके प्रति गहरी श्रद्धा व सम्मान के साथ 'प्रिय नेता कॉमरेड बादशाह खान लाल सलाम' 'प्रिय नेता कॉमरेड बादशाह खान हम तुम्हे भूलेगें नहीं' नारों के साथ दुर्ग स्थित हरनाबांधा शमशान में ले जाया गया। वहाँ पर भी फूल चढ़ाकर श्रद्धांजली देते हुए, अंतिम दर्शन करते हुए, बड़े ही दुख, अफसोस व शोक के साथ उन्हें विदा किया।

कॉमरेड बादशाह खान लाल सलाम!

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. सत्यवान द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631 Email : sarvaharadrishtikon@yahoo.com